

W-14340

R. 9806

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

No. 165]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2004/चैत्र 9, 1926

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2004/CHAITRA 9, 1926

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2004

सा.का.नि. 232(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

“सं0आ0 201”

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2004

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2004 है।
2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2003 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि पर नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (13) तक में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट राशियां, उन स्तम्भों में उल्लिखित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को उन्नत करने और “विशेष समस्याओं” के लिए कार्यक्रमों पर राजस्व और पूंजी प्रकृति के व्यय के लिए, भारत होंगी, अर्थात् :-

सारणी
निम्नलिखित से संबंधित स्तरों को उन्नत करने के लिए

राज्य	जिला प्रशासन	पुलिस प्रशासन	कारागार प्रशासन	अग्नि	न्यायिक	स्वास्थ्य	प्रारंभिक शिक्षा	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	सार्वजनिक पुस्तकालय	विरासत संरक्षण	पर्यावरणिक स्रोतों की वृद्धि	विशेष समस्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						(रुपए लाख में)						
आंध्र प्रदेश	..	915.25	158.90	153.57	..	172.08	1513.17	248.90	2127.60	950.71
अरुणाचल प्रदेश	44.52	33.21	153.24	232.95
असम	..	436.07	..	248.90	497.80	298.93	..	399.72	364.15	1113.11
बिहार	233.27	511.90	1244.70
छत्तीसगढ़	1063.21	79.00
गोवा	20.11	226.07
गुजरात	..	754.12	271.48
हरियाणा	..	316.60	296.70	124.00	172.00	286.84	456.82
हिमाचल प्रदेश	49.78	149.34	81.44	..	49.78	..	237.62	..	492.82	1841.20
जम्मू-कश्मीर	60.32
कर्नाटक	597.36	..	422.31	401.80	1060.79	..
केरल	..	738.28	226.25	..	113.31	313.02	29.67	209.38	..	99.56	191.37	2489.00
मध्य प्रदेश	3288.14	1445.95	293.70	1028.45	..	1147.75	..	963.24	..	122.12	2123.86	3288.50
महाराष्ट्र	2177.30	639.56
मणिपुर	..	155.66	49.78	180.99	..	309.39	150.82
नागालैंड	..	613.16	20.11	49.78	..	220.19	20.11	49.78	100.51	100.55
उड़ीसा	..	686.79	62.84	429.33	442.42	389.13	..	497.80	819.08	2939.00
राजस्थान	..	1481.02	836.10	611.33
सिक्किम	..	55.09	79.94	19.62	19.64	89.01	49.78	137.51	..	5.10	62.72	..
तमिलनाडु	1530.32	1235.47	398.24	136.66	..	211.15	452.07	497.80	919.42	2438.22
त्रिपुरा	..	165.46	10.58	49.78	49.78	..	89.62	20.11	..	758.24
उत्तर प्रदेश	1633.50	2003.97	184.07	797.97	4420.18	1679.08
उत्तरांचल	1063.92	201.21	4.83	623.51	181.42	247.82	47.36	152.93	490.80
पश्चिमी बंगाल	181.43	..	2641.12	311.94

परन्तु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट और राज्य स्तरीय सशक्त समितियों द्वारा अनुमोदित सेक्टरों और सेवाओं के प्रशासन से संबंधित स्तरों को उन्नत करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों पर खर्च की जाएंगी :

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट वर्ष के लिए उपयोग न किए गए अनुदान को आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत किया जा सकेगा और ऐसा अनुदान जिसका उपयोग नहीं किया गया है, वर्ष 2004-2005 के दौरान ऐसी प्रोत्साहन निधि में जमा किया जाएगा जिससे सभी राज्यों को राजवित्तीय निष्पादन पर आधारित अनुदान किए जाने हैं :

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्रशासन से संबंधित ऐसे अनुमोदित कार्यक्रम या कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय, जो उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, उस प्रशासन के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट अनुदान की राशि से कम है, तो इस प्रकार अधिक संदत्त राशि का किसी ऐसी राशि या राशियों के विरुद्ध, जो उस राज्य को किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी उत्तरवर्ती वर्ष में संदेय हो सकती है, समायोजन किया जाएगा ।

(2) उपपैरा (1) के अधीन संदेय कोई राशि या राशियां अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परन्तुकों में से प्रत्येक के अधीन राज्यों को संदेय किसी राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी ।

[फा. सं. 19(3)/2004-वि. 1]

टी.के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2004

G.S.R. 232(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

“C.O.201”

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 3 ORDER, 2004

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2004.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2003, as grants-in-aid of the revenues to each of the States specified in column (1) of the Table below, the sums specified against it in each of the columns (2) to (13) of the said Table, towards expenditure of revenue and capital nature, on programmes for upgradation of standards and “special problems” relating to the administration of the sectors and services mentioned in those columns, namely:—

TABLE
For upgradation of Standards relating to

State	District Adminis- tration	Police Adminis- tration	Jail Adminis- tration	Fire	Judicial	Health	Elementary Education	Computer Training	Public Libraries	Heritage Protection of	Augmentation of Traditional Water Sources	Special Problem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					(Rupees in lakhs)							
Andhra Pradesh	...	915.25	158.90	153.57	...	172.08	1513.17	248.90	2127.60	950.71
Arunachal Pradesh	44.52	33.21	153.24	232.95
Assam	...	436.07	...	248.90	497.80	298.93	...	399.72	364.15	1113.11
Bihar	233.27	511.90	1244.70
Chhattisgarh	1063.21	79.00
Goa	20.11	226.07
Gujarat	...	754.12	271.48
Haryana	...	316.60	296.70	124.00	172.00	286.84	456.82
Himachal Pradesh	49.78	149.34	81.44	...	49.78	...	237.62	...	492.82	1841.20
Jammu and Kashmir	60.32
Karnataka	597.36	...	422.31	401.80	1060.79	...
Kerala	...	738.28	226.25	...	113.31	313.02	29.67	209.38	...	99.56	191.37	2489.00
Madhya Pradesh	3288.14	1445.95	293.70	1028.45	...	1147.75	...	963.24	...	122.12	2123.86	3288.50
Maharashtra	2171.30	639.56
Manipur	...	155.66	49.78	180.99	...	309.39	150.82
Nagaland	...	613.16	20.11	49.78	...	220.19	20.11	49.78	100.51	100.55
Orissa	...	686.79	62.84	429.33	442.42	389.13	...	497.80	819.08	2939.00
Rajasthan	...	1481.02	836.10	611.33
Sikkim	...	55.09	79.94	19.62	19.64	89.01	49.78	137.51	...	5.10	62.72	...
Tamil Nadu	1530.32	1235.47	398.24	136.66	...	211.15	452.07	497.80	919.42	2439.22
Tripura	...	165.46	10.58	49.78	49.78	...	89.62	20.11	...	758.24
Uttar Pradesh	1633.50	2003.97	184.07	797.97	4420.18	1679.08
Uttaranchal	1063.92	201.21	4.83	623.51	181.42	247.82	47.36	152.93	490.80
West Bengal	181.43	...	264.12	311.94

Provided that the sums specified above shall be expended on programmes formulated by the State Governments for upgradation and standards relating to the administration of the sectors and services specified above and approved by State Level Empowered Committees:

Provided further that the unutilised grant for a particular year may be carried forward to next year and the grant which remain unutilised will be credited to the Incentive Fund during 2004-05 from which fiscal performance based grants are to be released to all the States:

Provided also that if the actual expenditure on such approved programmes relating to any administration as revealed in the accounts of that year is lower than the amount of grant specified above against that administration, the amount so paid in excess shall be adjusted against any sum or sums which may become payable to that State in any of the succeeding years for any other purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) shall be in addition to any sum or sums payable to the States under each of the provisos to clause (1) of article 275.

[F. No. 19(3)/2004-L. 1]

T. K. VISWANATHAN, Secy.

1084 GI/04-2